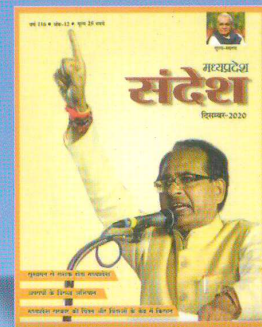
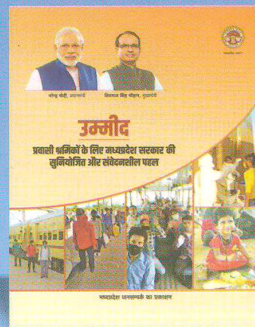


वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21



मध्यप्रदेश शासन



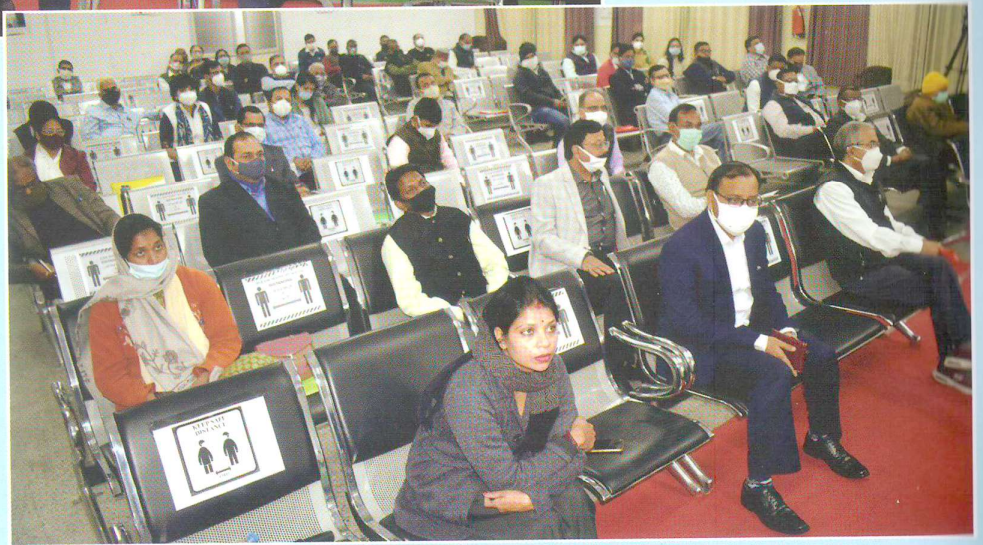
जनसम्पर्क विभाग

www.mpinfo.org/www.mpnewsarch.org
www.dprftp.com & District News Portal - www.dprmp.org





जनसंपर्क अधिकारियों के दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में 14-15 एवं 16-17 दिसम्बर, 2020 को हुआ। प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री शिवशेखर शुक्ला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

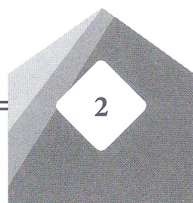




मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग



जनसम्पर्क विभाग

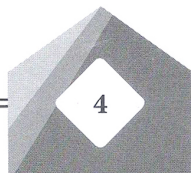
विभागीय मंत्री
शिवराज सिंह चौहान

प्रमुख सचिव
शिवशेखर शुक्ला

आयुक्त
डॉ. सुदाम खाड़े

संचालक
आशुतोष प्रताप सिंह

अपर सचिव
डॉ. एच.एल. चौधरी



विभागीय संरचना कार्यालय

संचालनालय मुख्यालय	01	भोपाल
संभागीय कार्यालय	07	इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा
जिला कार्यालय	44	
राज्य के बाहर स्थापित कार्यालय	02	1. म.प्र. सूचना केन्द्र नई दिल्ली 2. म.प्र. सूचना केन्द्र मुम्बई
विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपक्रम/संस्था	02	1. मध्यप्रदेश माध्यम 2. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
स्वीकृत पद		
प्रथम श्रेणी	-	53
द्वितीय श्रेणी	-	78
तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	-	248 (20 सांख्येत्तर पदों सहित)
तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	-	232
चतुर्थ श्रेणी	-	251
कुल	-	862

विभागीय दायित्व

जनसम्पर्क विभाग का मुख्य दायित्व सरकार की नीतियों, निर्णयों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी प्रचार-प्रसार माध्यमों से लोगों तक पहुँचाना और जन-मानस में शासन की उज्ज्वल छवि प्रस्तुत करना है। विभाग की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

समाचार प्रभाग

शासन के कार्यक्रमों, नीति संबंधी सूचनाओं और विकासात्मक गतिविधियों पर आधारित समाचार, विशेष लेख, सफलता की कहानियाँ, फोटो-वीडियो कव्हेरेज करवाकर समाचार-पत्रों, दूरदर्शन, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स के साथ सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रकाशन और प्रसारण के लिए प्रतिदिन भेजे जाते हैं। विभागीय गतिविधियों की जानकारी के लिए सभी विभागों में अलग-अलग जनसंपर्क अधिकारी संबद्ध हैं।

वर्ष 2020 में प्रतिवेदित अवधि तक 4964 हिन्दी समाचार, 1537 अंग्रेजी समाचार, 42 विशेष लेख प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रकाशन एवं प्रसारण के लिये जारी किये गये। हिन्दी में जारी मुख्य एवं विशेष समाचार/आलेख में से 3904 समाचार/ आलेख उर्दू भाषा में भी जारी किये गये। तीनों भाषाओं में जारी समाचार, विशेष आलेख और सफलता की कहानियों को फोटो-वीडियो सहित जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.mpinfo.org पर निरंतर अपलोड किया गया।

संभागीय एवं जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा इस अवधि में एक लाख 70 हजार 604 समाचार/ सफलता की कहानियाँ जारी की गईं। प्रतिदिन जारी होने वाले समाचार/ सफलता की कहानियाँ फोटो सहित प्रतिदिन डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल www.dprmp.org पर अपलोड किये जाते हैं।

विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के कार्यालय में पत्रकार वार्ताओं के आयोजन के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता जागरूकता अभियान, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी समाचार जारी किये गये। मीडियाकर्मियों को उप- निर्वाचन वाले जिलों के मतदान एवं मतगणना प्राधिकार-पत्र जारी किये गये।

प्रतिवेदित अवधि में गणतंत्र दिवस के लिये माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री के और स्वतंत्रता दिवस के लिये माननीय मुख्यमंत्री के संदेश तैयार किये गये।

प्रतिवेदित अवधि में मा. मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री-परिषद के सदस्यों सहित अन्य विभाग प्रमुखों के लिये समय-समय पर प्रेस ब्रीफिंग और पत्रकार-वार्ताओं का आयोजन किया गया।

समाचार शाखा में कार्यरत अधिकारियों को लेखन की गुणवत्ता के साथ सामयिक विषयों पर लेखन कार्य एवं मीडिया से समन्वय का प्रशिक्षण दिलवाया गया। इन प्रयासों के तहत प्रोफेशनल तरीका अपनाकर समाचार के संचयन और लेखन में पत्रकारों के नजरिये को तरजीह दी गई। समाचार-पत्रों में "प्रेस-नोट" को उल्लेखनीय स्थान मिले, इसके लिये निरंतर प्रयास किये गये। इससे राष्ट्रीय स्तर तक की मीडिया में मध्यप्रदेश सरकार के क्रियाकलापों को प्रमुखता मिल रही है।

समाचारों में विविधता और नयापन लाने की कोशिशें लगातार की जाती हैं। इस संबंध में अधिकारियों को समय-समय पर मार्ग-दर्शन भी दिया गया। कोरोना काल में शासन-प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं और उपचार के

लिये किये गये प्रबंधों को संचार के सभी माध्यमों से प्रचारित-प्रसारित किया गया। साथ ही आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के विकास रोडमैप और उसके अंतर्गत की जा रही गतिविधियों का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

संचार प्रभाग

प्रतिवेदित अवधि में विभाग की आंतरिक संचार प्रणाली को विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ किया गया। विज्ञापन प्रभाग द्वारा प्रतिदिन समाचार-पत्रों को जारी किये जाने वाले शासकीय निविदा और प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। विभागों से प्राप्त होने वाले विज्ञापन ऑनलाइन ही संचालनालय को प्राप्त हो रहे हैं। ऑनलाइन विज्ञापन एवं आर.ओ. जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर (dpradvt.mpinfo.org) का निर्माण किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों पर राष्ट्रीय/प्रादेशिक और स्थानीय स्तर के प्रसारित बुलेटिनों के दृष्टिगत विभिन्न घटनाक्रमों/गतिविधियों संबंधी न्यूज की सतत मॉनिटरिंग और रिकार्डिंग के लिए मुख्यालय में स्थापित मॉनिटरिंग सेल में 24 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय चैनलों के न्यूज बुलेटिनों और प्रदेश पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की गई।

राज्य शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन के कार्यक्रमों की लाईव स्ट्रीमिंग कव्हेरेज का कार्य एजेंसी ए.एन.आई., नई दिल्ली को दिया गया है। इस न्यूज एजेंसी के अंतर्गत 400 टी.वी. चैनल्स और एक हजार से अधिक समाचार-पत्र और न्यूज पोर्टल है। यह एजेंसी राज्य सरकार के कार्यक्रमों का लाईव ब्राडकास्टिंग का कार्य करती है। यह लाईव इवेंट की एक्टिव लिंक सोशल मीडिया तथा अन्य मीडिया प्लेटफार्मों के लिये उपलब्ध कराती है।

सोशल मीडिया

जनसंपर्क विभाग के सोशल मीडिया विंग ने अपने गठन के तीसरे साल में भी काफी तत्परता, सतर्कता और जिम्मेदारियों के साथ शासकीय समाचारों और गतिविधियों को लोगों तक पहुँचाया है। साल 2020 के कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया उपयोगी रहा। इस दौरान कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयासों और कार्रवाइयों से संबंधित सही जानकारी सोशल मीडिया के जरिए आसानी से आम जन तक पहुँचाई गई। कोरोना काल में विभाग के सोशल मीडिया विंग द्वारा प्रदेश के बाहर फँसे लोगों को सोशल मीडिया पर मांगी गई जानकारीयों उपलब्ध कराई गई।

सोशल मीडिया विंग द्वारा वर्तमान में 402 सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन किया जा रहा है। इनमें मुख्यमंत्री कार्यालय, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश, 47 शासकीय विभाग, समस्त संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर, संभागीय एवं जिला जनसंपर्क अधिकारियों के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स शामिल हैं। प्रतिवेदित वर्ष में विंग के द्वारा सीएमओ मध्यप्रदेश के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट और यू-ट्यूब चैनल तैयार कर इन अकाउंट्स को भी सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर अक्सर शासन की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फेक न्यूज वायरल किये जाते हैं। जिनके अत्याधिक वायरल हो जाने की स्थिति में शासन को लेकर आमजन में नकारात्मक भाव पैदा होते हैं। अब तक जनसंपर्क विभाग के सोशल मीडिया हैंडल्स से ऐसे वायरल फेक न्यूज का खंडन किया जाता है। लेकिन, नवाचार करते हुए सोशल मीडिया विंग द्वारा पृथक से जनसंपर्क फैक्ट चेक के नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स तैयार किये गये

हैं। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से वायरल हो रहे फेक न्यूज को काउंटर कर आमजन को सही और सटीक समाचार उपलब्ध कराया जाएगा।

कोरोना काल और उससे उत्पन्न स्थितियों के बाद देश "आत्म-निर्भर भारत" की ओर अग्रसर हुआ है। आत्म-निर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने "आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश" बनाने की घोषणा की। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान को लेकर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 4 दिवसीय वेबिनार भी आयोजित किया गया। इस वेबिनार का सोशल/डिजिटल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। चार दिवसीय वेबिनार को सोशल मीडिया के समस्त प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया। वेबिनार में शिरकत कर रहे गणमान्य लोगों द्वारा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के बारे में दिए गए सुझावों और संभावनाओं पर लाइव ट्वीट पोस्ट किये गये। #AatmaNirbharMadhyaPradesh के साथ शासकीय सोशल मीडिया हैंडल्स पर अब तक एक हजार से अधिक ट्वीट पोस्ट किये जा चुके हैं।

विभागीय अधिकारी सोशल मीडिया पर बेहतर तरीके से काम कर सकें, इसके लिए प्रतिवेदित अवधि में उन्हें पुनः प्रशिक्षित किया गया। जनसंपर्क संचालनालय में पदस्थ समस्त जनसंपर्क अधिकारियों में से प्रतिदिन दो अधिकारियों को सोशल मीडिया विंग में आमंत्रित कर अपडेटेड फीचर्स से अवगत कराया गया। 15 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनसंपर्क अधिकारियों ने भी दिलचस्पी दिखाई और गहरी रुचि के साथ ट्रेनिंग मॉड्यूल का अध्ययन किया।

प्रतिवेदित अवधि तक विभाग द्वारा संचालित सभी फेसबुक पेजों पर 47.03 लाख से अधिक लाइक और ट्वीटर अकाउंट्स पर 29.22 लाख से अधिक फॉलोअर रहे। पिछली प्रतिवेदित अवधि की तुलना में इस प्रतिवेदित वर्ष में ये आंकड़ा 114 प्रतिशत अधिक है। सोशल मीडिया विंग द्वारा प्रतिवेदित अवधि में 9 हजार 103 ग्राफिक्स और 4000 से अधिक वीडियो प्रोजेक्ट्स तैयार किये गये। इसके आधार पर शासकीय गतिविधियों और योजनाओं का सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रचार-प्रसार किया गया।

सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई शासकीय गतिविधियों का लाइव प्रसारण किया जाता है। प्रदेश के समस्त जिलों में समय-समय पर आयोजित होने वाले शासकीय कार्यक्रमों को सोशल मीडिया लाइव के जरिए आम लोगों तक पहुँचाया जाता है। प्रतिवेदित अवधि में समस्त शासकीय अकाउंट्स को मिलाकर सोशल मीडिया पर 1200 से अधिक लाइव किये गये हैं, जिसकी रीच/इम्प्रेशन करोड़ों में प्राप्त हुई है।

सोशल मीडिया विंग द्वारा सप्ताह में पाँच दिन जनसम्पर्क खबरें, 10 संभाग-10 खबरें बुलेटिन जारी कर शासन की गतिविधियों से लोगों को अवगत कराया गया। माननीय मुख्यमंत्री की दैनिक गतिविधियों के आधार पर सीएम टूडे नाम से एक पृथक वीडियो बुलेटिन जारी किया जाता है।

जनसम्पर्क के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 'क्या आप जानते हैं?' शीर्षक से एक ग्राफिकल सेगमेंट प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें जन हितैषी निर्णयों की जानकारी प्रचारित-प्रसारित की जा रही है।

विभाग के सोशल मीडिया हैंडल्स पर 'Explore MP' नाम से भी ग्राफिकल सेगमेंट प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से आम लोगों को मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयों पर हितग्राहियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित वीडियो सेगमेंट "खुशियों की दास्तां" सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नियमित रूप से प्रचारित-प्रसारित की जाती है। प्रतिवेदित अवधि में 550 से अधिक "खुशियों की दास्तां" सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रसारित की गई।

जनसंपर्क के यूट्यूब चैनल पर 56 हजार से अधिक सब्सक्राइबर प्रतिवेदित अवधि में रहे हैं। इस चैनल पर नियमित तैयार किये जाने वाले बुलेटिन, आयोजन विशेष पर तैयार किये जाने वाले स्पेशल वीडियो पैकेज, डिपार्टमेंट के कार्यों से संबंधित पैकेज अपलोड किये गये। इसके अलावा समय-समय पर इस चैनल में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया गया है।

विभाग द्वारा युवाओं के लोकप्रिय रोजगारोन्मुख साप्ताहिक समाचार-पत्र 'रोजगार और निर्माण' का ई पेपर एडीशन वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। शासन संबंधी गतिविधियों की जानकारी देने वाली मासिक पत्रिका 'मध्यप्रदेश संदेश' भी ई-मैगजीन के रूप में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा विभाग द्वारा प्रतिदिन के समाचारों पर आधारित 'जनसम्पर्क टूडे' नाम से ई-न्यूज लेटर जारी किया गया।

समस्त सोशल मीडिया अकाउंट्स को शामिल कर www.jansamparkmp.com वेबसाइट भी संचालित की जा रही है। इस वेबसाइट पर प्रदेश के सोशल मीडिया नेटवर्क की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

वेबसाइट

विभाग की मुख्य वेबसाइट www.mpinfo.org को समय-समय पर नवीनतम टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपडेट किया जाकर मोबाइल, टेबलेट और अन्य डिवाइस आधारित बनाया गया। इस साइट पर हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत सहित चार भाषाओं में समाचार/लेख आदि उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन जारी किये जाने वाले समाचार, जन-कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लेख, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश और विजन टू डिलीवरी, माननीय मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विजुअल्स, मंत्रि-परिषद के निर्णय, साप्ताहिक मध्यप्रदेश "रोजगार और निर्माण", मासिक "मध्यप्रदेश संदेश", शासकीय विभागों की नीतियाँ, शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण अभियान, कला एवं संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक स्थलों की जानकारी, विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रदर्शन विज्ञापन, निविदा, अधिमान्यता, पत्रकार दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना, पत्रकार पुरस्कार योजना, मीडिया प्रतिनिधि कल्याण सहायता संबंधी नियम, अचल सम्पत्ति के विवरण, नवीन सूचनाएँ, विभागीय लोक सूचना एवं अपीलीय अधिकारियों की सूची, विज्ञापन के रिलीज ऑर्डर और सम-सामयिक संदर्भ के साथ ही मंत्रि-परिषद्, प्रशासनिक अधिकारियों और विभाग के मुख्यालय तथा फील्ड अधिकारियों की सूची तथा विभिन्न विभागों के ई-मेल और पते उपलब्ध हैं।

साइट पर सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्वीटर एवं यू-ट्यूब) संबंधी विभागीय गतिविधियाँ भी प्रदर्शित हैं। अब यह साइट पहले से बेहतर और यूजर फ्रेंडली हो गई है। साइट को प्रतिवेदित अवधि में 27 करोड़ 81 लाख 85 हजार 789 हिट्स प्राप्त हुए।

जिलों के समाचारों के लिये डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल www.dprmp.org कार्यरत है। पोर्टल पर जनवरी, 2020 से दिसम्बर 2020 की अवधि में 1 लाख 70 हजार 604 समाचार अपलोड किये गये। इस पोर्टल को प्रतिवेदित अवधि में 20 करोड़ 71 लाख 5 हजार 81 हिट्स प्राप्त हुए। राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय समाचार-पत्र, पत्रिकाओं की क्लिपिंग देखने के लिये कार्यरत विभागीय वेबसाइट www.mpnewsarch.org को भी आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाकर यूजर्स फ्रेंडली बनाया गया। इस साइट को भी प्रतिवेदित अवधि में 37 लाख 29 हजार 613 हिट्स मिले।

फोटो-फिल्म प्रभाग

प्रभाग द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण के अतिरिक्त अन्य सभी शासकीय कार्यक्रमों/आयोजनों/बैठकों के वीडियो/फोटो कव्हेरेज तथा आवश्यकतानुसार छायाचित्रों के एलबम तैयार करवाये जाते हैं।

विभाग द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण एवं सभी शासकीय कार्यक्रमों/आयोजनों के वीडियो कव्हेरेज करवाकर प्रतिदिन दूरदर्शन एवं अन्य स्थानीय टी.व्ही. चैनल को प्रसारण के लिये विभागीय वेबसाइट और यू-ट्यूब पर अपलोड किये जाते हैं। इस दौरान 1626 वीडियो कव्हेरेज प्रसारण के लिये भेजे गये।

प्रतिवेदित अवधि में शासकीय कार्यक्रमों के फोटो कव्हेरेज के छाया-चित्र वेबसाइट और यू-ट्यूब पर अपलोड किये गये। संभागीय एवं जिला कार्यालयों के भी छायाचित्रों को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजा गया। इस अवधि में मुख्यालय द्वारा 1584 फोटो कव्हेरेज करवाये गये।

फिल्म-निर्माण प्रभाग

फिल्म-निर्माण प्रभाग द्वारा प्रतिवेदित अवधि में 42 वीडियो स्पॉट बनाये गये। इनमें कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता एवं बचाव के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास, कोरोना वारियर्स, कोरोना संघर्ष से जुड़े योद्धाओं की सुरक्षा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनता के हित में लिये गये निर्णय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, श्रमिकों के लिये रोजगार एवं घर वापसी में सहयोग, जीवन शक्ति योजना, संबल योजना, मंडी एक्ट में संशोधन- किसानों के हित में, कोरोना से डरे नहीं जन जागरूकता अभियान, पंच परमेश्वर योजना, चम्बल प्रोग्रेस वे, रोजगार सेतु, ग्रामीण पथ व्यवसायी योजना, आत्म-निर्भर म.प्र. गीत, मेधावी विद्यार्थियों को लेपटाप तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों में उप चुनाव हेतु मतदाता जागरूकता अभियान, विषय शामिल हैं। इन वीडियो स्पॉट का विभिन्न प्रादेशिक चैनलों पर प्रसारण करवाया गया है।

संदर्भ प्रभाग

प्रभाग द्वारा विभिन्न विषय-विशेष की चयनित पुस्तकें प्रदेश भर के जिला एवं संभागीय जनसम्पर्क कार्यालयों एवं नई दिल्ली / मुम्बई स्थित सूचना केन्द्रों को संदर्भ के लिए भेजी जाती हैं। भोपाल में लोकसेवा के रूप में सूचना केन्द्र न्यू मार्केट स्थित जी.टी.बी. कॉम्पलेक्स में संचालित है। निःशुल्क संचालित यह सूचना केन्द्र प्रतिदिन दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक आमजन के लिए खुला रहता है।

संदर्भ प्रभाग में विभिन्न विषय-विशेष की पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये पुस्तकें समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन, पठन-पाठन तथा संदर्भ के उपयोग में आती हैं।

वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संदर्भ प्रभाग की लायब्रेरी का डिजिटাইजेशन का कार्य शुरू किया गया है। इसी क्रम में लायब्रेरी की लगभग 22 हजार पुस्तकों की बार कोडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। डिजिटাইजेशन से संदर्भ शाखा की वेबसाइट www.dpriib.com पर पुस्तकों की उपलब्धता देखी जा सकेगी। शेष कार्य भी प्रगति पर है।

विज्ञापन प्रभाग

विज्ञापन प्रभाग द्वारा राज्य शासन के सभी विभाग/कार्यालय की निर्माण/निविदा/ भर्ती सूचनाओं का समाचार-पत्रों में विज्ञापन के रूप में वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशन करवाने का कार्य दिनांक 15 जुलाई 2020 से ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार प्रदर्शन विज्ञापन का ऑनलाइन कार्य दिनांक 15 सितम्बर, 2020 से प्रारंभ किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रदर्शन विज्ञापन के माध्यम से प्रिंट मीडिया एवं न्यूज कैप्सूल/वीडियो स्पॉट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार-प्रसार करवाने के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2020 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत दूरदर्शन/आकाशवाणी, विविध भारती, टी.वी. न्यूज चैनलों, प्राइवेट रेडियो और एफ.एम. चैनलों, कम्युनिटी रेडियो, वेबसाइट/वेबपोर्टल, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों का प्रसार-प्रसार कराया गया। विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना, कोरोना वारियर्स सेवा सम्मान, किसानों को बीमा राशि का सिंगल क्लिक से वितरण आदि का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

पारदर्शिता और सुगमता की दृष्टि से वर्गीकृत तथा प्रदर्शन विज्ञापन सामग्री और विज्ञापन आदेश ऑनलाईन जारी किये जाते हैं। विज्ञापन प्रभाग द्वारा विज्ञापन देयकों के ऑनलाईन भुगतान के साथ ही विज्ञापन आदेश एवं विज्ञापन सामग्री भी ऑनलाईन दी जा रही है। इसको और अधिक उन्नत करते हुए विभिन्न विभागों के लिये कम्प्यूटर प्राणाली को विकसित किया जा रहा है।

कैलेंडर वर्ष 2020 में कुल 10 हजार 333 विज्ञापन जारी किये गये। इनमें 9 हजार 299 वर्गीकृत और 1034 प्रदर्शन विज्ञापन शामिल हैं।

प्रकाशन प्रभाग

जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी, नीतियों और कार्यक्रमों का आईना होते हैं। प्रदेश की लोकहितकारी नीतियों, योजनाओं और प्रदेश के जीवन तथा समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशनों का कार्य संचालनालय की प्रकाशन शाखा द्वारा किया जाता है। इन प्रकाशनों में किताबें, लघु पुस्तिकाएँ, फोल्डर, पैम्फलेट्स और पोस्टर तथा मासिक पत्रिका "मध्यप्रदेश संदेश" शामिल हैं।

मध्यप्रदेश संदेश

प्रदेश सरकार की आमुख पत्रिका "मध्यप्रदेश संदेश" हर माह प्रकाशित होने वाली नियमित पत्रिका है। संदेश का प्रत्येक अंक एक समयानुकूल आवरण कथा पर केन्द्रित किया जा रहा है। पत्रिका में मुख्यतः प्रदेश की जन-कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनके परिणामों पर केन्द्रित सामग्री प्रकाशित की जाती है। पत्रिका को नये कलेवर के साथ प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष लेखों का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अलावा इस पत्रिका में प्रदेश की विशिष्टताओं, विभिन्नताओं और विलक्षणताओं पर तथा प्रदेश के जीवन और समाज, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्व, तीज-त्यौहार, परम्पराओं, लोक जीवन, वन और वन्य-जीवन, पर्यटन, खेल, सिनेमा तथा साहित्यिक गतिविधियों और प्रदेश से जुड़े विशिष्ट व्यक्तित्वों एवं विकास की विभिन्न अवधारणाओं पर वरिष्ठ और युवा लेखकों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। "मध्यप्रदेश संदेश" पत्रिका ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है। मध्यप्रदेश संदेश की पहुँच आसान बनाने और बढ़ाने के लिये इसके अंतिम कवर पर QR कोड लगाया जा रहा है।

लोकहित के कार्यों का प्रकाशन

मध्यप्रदेश सरकार के जन-कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दूर-सुदूर गाँवों में रहने वाले लोगों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकाशन किए गए। इन प्रकाशन को जिला मुख्यालयों पर स्थित जनसंपर्क कार्यालयों के माध्यम से जन-सामान्य तक पहुँचाया गया है। इसके अलावा ऐसे विशिष्ट आयोजनों में इन प्रकाशनों का वितरण किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में जन-समुदाय उपस्थित था।

पिछले एक वर्ष में- 'मध्यप्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय', 'उम्मीद- प्रवासी श्रमिकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार की सुनियोजित और संवदेनशील पहल', 'आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप-2023' और 'संदर्भ- मध्यप्रदेश-2020', 'मध्यप्रदेश- आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ते कदम' आदि पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। साथ ही, 'आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश' फोल्डर तथा 'किसानों के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश सरकार', 'मुख्यमंत्री का किसानों के नाम पत्र', 'हमारे किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता' एवं 'मध्यप्रदेश में कृषि और किसान कल्याण' पैम्फलेट्स का प्रकाशन किया गया है।

पत्र-परिनिरीक्षण प्रभाग

पत्र-परिनिरीक्षण प्रभाग द्वारा कैलेंडर वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के बावजूद (शासन की गाइड-लाइन का पालन करते हुए) बिना किसी व्यवधान के शाखा में प्रतिदिन संपादित होने वाले सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।

प्रतिवेदित अवधि में शासन के सभी प्रमुख स्तरों पर समाचार-पत्रों के नियमित प्रदाय के साथ-साथ महत्वपूर्ण न्यूज क्लीपिंग्स के फोटो कॉपी बंच तैयार कर भेजे गये। लगभग 81 लाख 37 हजार समाचार-पत्र न्यूज क्लीपिंग्स भेजी गयी हैं। क्ली

पत्र-परिनिरीक्षण प्रभाग में संचालित NMMSA एप्लीकेशन व्यवस्था के तहत प्रतिदिन प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त होने वाली समाचार-पत्रों की न्यूज क्लीपिंग्स का परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है। आधारहीन तथ्यों वाले नकारात्मक समाचारों का, संबंधित विभाग से जानकारी, वस्तुस्थिति प्राप्त कर खंडन अथवा समान्तर समाचार जारी करना इस व्यवस्था का उद्देश्य है। उत्कृष्ट स्तर के सकारात्मक समाचारों के आधार पर प्रदेश स्तर पर उस तरह के प्रयास किये जाने का प्रस्ताव दिया जाता है।

प्रतिवेदित अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन के 100 दिन, रोडमैप (आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश), रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना, विधानसभा उपचुनाव तथा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समाचार-पत्र न्यूज क्लीपिंग्स की रंगीन फोटो कॉपी करवाकर उनकी स्पोर्ट्स बाइंडिंग तैयार कर उपलब्ध करायी गयी।

विगत विधानसभा उपचुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पृथक न्यूज क्लीपिंग्स यूनिट स्थापित कर उप चुनाव संबंधी सभी समाचार-पत्र न्यूज क्लीपिंग्स को उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रभाग द्वारा किया गया।

पंजीयन प्रभाग

पंजीयन प्रभाग में प्रदेश के सभी जिलों से प्रकाशित हो रहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार-पत्रों के साथ ही मासिक, त्रैमासिक तथा अन्य नियतकालिक पत्र-पत्रिका को एक वर्ष तक जिलेवार संधारित किया जाता है।

कालखण्ड माह जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक 499 दैनिक समाचार-पत्र, 488 साप्ताहिक समाचार-पत्र, 89 पाक्षिक पत्र/पत्रिका, 499 मासिक पत्र/पत्रिका एवं 49 त्रैमासिक पत्र/पत्रिका पंजीयन शाखा में प्राप्त हुए।

प्रतिवेदित अवधि में उपरोक्त समाचार-पत्र/पत्रिकाओं का पंजीयन शाखा में संधारण किया गया।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

क्षेत्र प्रचार प्रभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकासात्मक उपलब्धियों एवं कार्यक्रम को आमजन तक पहुँचाने के लिए आउटडोर ब्रांडिंग एवं आधुनिक जन-संचार के माध्यमों से निम्नानुसार प्रचार-प्रसार किया गया:-

- प्रभाग में आउटडोर पब्लिसिटी के विभिन्न प्रचार कार्यों के लिए ई-टेण्डर की कार्यवाही की गई।
- प्रचार अभियानों का आयरन फ्रेम बोर्ड, एलडी फॉम कैलेण्डर से प्रचार-प्रसार किया गया।
- कोविड-19 के दौरान क्वारंटाइन केन्द्रों, पैरामेडिकल, मेडिकल एवं पुलिसकर्मियों के विश्रामस्थलों पर कोविड 19 के प्रति जागरूकता संबंधी एवं मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान कोविड-19 से बचकर किस प्रकार मतदान करना है एवं मतदाता जागरूकता के दिशा-निर्देशों का आयरन फ्रेम बोर्ड, दीवार लेखन, प्रचार रथ एवं ऑटो रिक्षा के पीछे विनाई स्टीकर के द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया।
- विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान प्रत्येक जिलों के मतदान केन्द्रों पर उनकी मांग के अनुसार लाइट, माईक, टेन्ट, शामियाना स्थापित करने का कार्य किया गया।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल जीवन मिशन योजना का ग्रामीण स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया।

प्रस्तावित नीति

मैदानी प्रचार कार्यों में पारदर्शिता लाने, नये प्रचार माध्यमों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा समय की आवश्यकता, कार्य की महत्ता और क्षेत्र प्रचार की व्यापकता को देखते हुए "क्षेत्र प्रचार नीति" तैयार की गई है। इसमें सभी जरूरी प्रावधान होंगे, जो भविष्य में जनसंपर्क संचालनालय एवं मध्यप्रदेश माध्यम पर लागू होंगे। इसके अंतर्गत बजट आवंटन की उपलब्धता, आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर ही प्रचार-प्रसार का कार्य किया जायेगा।

अधिमान्यता

अधिमान्यता नियम के अनुसार पत्रकारों को राज्य/जिला एवं तहसील-स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की जाती है। इसके लिये राज्य तथा संभागीय अधिमान्यता समितियाँ गठित हैं। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार इन समितियों के सदस्य होते हैं। राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति पत्रकारों के राज्य स्तरीय अधिमान्यता और संभाग-स्तरीय अधिमान्यता समिति पत्रकारों के जिला एवं तहसील स्तरीय अधिमान्यता संबंधी प्रकरणों में अनुशंसा करती है। वर्ष

2017 से अधिमान्यता कार्ड का नवीनीकरण/नवीन अधिमान्यता के लिये आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जा रहे हैं । मध्यप्रदेश में दिसंबर 2020 की स्थिति में 1158 राज्य स्तरीय, 2180 जिला स्तरीय एवं 915 तहसील स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं ।

पत्रकारों को आर्थिक सहायता

पत्रकारों को स्वयं एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को उपचार के लिए पात्रता और आवश्यकता के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है । इसके लिए मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति गठित है। प्राप्त सहायता आवेदनों पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार सहायता की कार्रवाई की जाती है । इसके तहत सामान्य बीमारियों के लिये 20 हजार रुपये तक एवं गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु अधिकतम 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसंबर 2020 तक 226 पत्रकारों को 94,05,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु पर उन पर आश्रित पत्नि और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि 4.00 लाख रुपये है । इसके तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसंबर माह तक 14 दिवंगत पत्रकारों के परिवार जनों को 54.00 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है ।

अनुदान

वर्ष 2020-21 में माधवराव सप्रे समाचार-पत्र संग्रहालय, भोपाल को 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

फैलोशिप

स्व. राजेन्द्र माथुर स्मृति पत्रकारिता फैलोशिप के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक पत्रकार को एक लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान है ।

पत्रकारिता सम्मान

मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिये उत्साहजनक वातावरण बनाये जाने और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अग्रणी पत्रकारों को सम्मानित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्रकारिता सम्मान प्रारम्भ किये गये हैं । यह सम्मान वर्ष 2016 तक के वितरित किये जा चुके हैं । पत्रकारों को विशिष्ट योगदान के लिये सम्मानित करने के उद्देश्य से नीचे दर्शाये अनुसार सम्मान स्थापित किये गये हैं :-

राष्ट्रीय सम्मान (सम्मान राशि 2.51 लाख रुपये)

- | | |
|---|------|
| 1. माणिकचन्द्र बाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान | (एक) |
| 2. गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान | (एक) |
| 3 विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान | (एक) |

राज्य स्तरीय सम्मान (सम्मान राशि 1.51 लाख रुपये)

- | | |
|--|------|
| 1. महेन्द्र चौधरी राज्य स्तरीय (फोटो) पत्रकारिता सम्मान | (एक) |
| 2. सत्यनारायण श्रीवास्तव, राज्य स्तरीय पत्रकारिता सम्मान | (एक) |

आंचलिक पत्रकारिता सम्मान (सम्मान राशि 1.01 लाख रुपये) (सात)

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. स्व. शरद जोशी सम्मान | भोपाल अंचल के पत्रकारों के लिये |
| 2. स्व. राहुल बारपुते सम्मान | इंदौर अंचल के पत्रकारों के लिये |
| 3. स्व. बनारसीदास चतुर्वेदी सम्मान | रीवा अंचल के पत्रकारों के लिये |
| 4. स्व. रतनलाल जोशी सम्मान | ग्वालियर अंचल के पत्रकारों के लिये |
| 5. स्व. जीवनलाल वर्मा विद्रोही सम्मान | जबलपुर अंचल के पत्रकारों के लिये |
| 6. स्व. कन्हैयालाल वैद्य सम्मान | उज्जैन अंचल के पत्रकारों के लिये |
| 7. स्व. मास्टर बलदेव प्रसाद सम्मान | सागर अंचल के पत्रकारों के लिये |

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय टेलीविज़न पत्रकारिता सम्मान

राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकारों एवं कैमरामेन के सम्मान के लिये भी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. राष्ट्रीय न्यूज चैनल (पत्रकार) सम्मान | राशि 1.51 लाख रुपये (एक) |
| 2. राष्ट्रीय न्यूज चैनल (कैमरामेन) सम्मान | राशि 1.01 लाख रुपये (एक) |
| 3. राज्य स्तरीय न्यूज चैनल (पत्रकार) सम्मान | राशि 1.51 लाख रुपये (एक) |
| 4. राज्य स्तरीय न्यूज चैनल (कैमरामेन) सम्मान | राशि 1.01 लाख रुपये (एक) |

सम्मान-निधि

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान-निधि की राशि 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये तथा आयु सीमा 62 से घटाकर 60 वर्ष की गई। वर्तमान में 203 पत्रकारों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान-निधि प्रदान की जा रही है।

लेप-टाप

शासन द्वारा राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेपटाप देने की योजना संचालित की जा रही है। इसके अर्न्तगत दिसंबर 2020 तक 864 राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेपटाप क्रय करने के लिये राशि का भुगतान किया जा चुका है।

संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

शासन द्वारा मध्यप्रदेश के संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना में स्वास्थ्य बीमा 2.00 एवं 4.00 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5.00 लाख एवं 10.00 लाख रुपये का है। योजना में दिसम्बर 2020 तक 3385 संचार प्रतिनिधि का बीमा हो चुका है।

पत्रकार प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश के जिलों/तहसीलों में पत्रकारों के लिये "मीडिया संवाद कार्यक्रम" किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यप्रदेश के जिलों में कार्यरत पत्रकारों को पत्रकारिता की कौशल बारीकियों पर चर्चा कर उन्हें नवीन तकनीक, प्रेस एक्ट और संविधान में उल्लेखित प्रेस से जुड़े कानूनों से परिचित कराना है।

आवास ऋण ब्याज अनुदान

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 05 वर्ष तक दिये जाने की योजना का क्रियान्वयन किया गया है। योजना के अन्तर्गत 18 पत्रकारों को राशि रुपये 16,94,241/- का ब्याज अनुदान स्वीकृत कर राशि उनके बैंक खाते में जमा कर दी गयी है।

विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपक्रम / संस्थाएँ

मध्यप्रदेश माध्यम

मध्यप्रदेश माध्यम की स्थापना जन-संचार के क्षेत्र में तेजी से होते बदलाव और नये समय में संचार की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग के सृजनात्मक उपक्रम के रूप में हुई है।

पिछले दो दशकों से अधिक समय से मध्यप्रदेश माध्यम, राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं के लिये संचार की सभी विधाओं में कार्य कर रहा है एवं आधुनिक समय के अनुरूप प्रचार कार्यों को नयी शक्ल देने में कामयाब रहा है। यह संस्था युवाओं के लिये साप्ताहिक "रोज़गार और निर्माण" के प्रकाशन के साथ शासकीय विभागों के लिये विभिन्न प्रकाशन और फिल्मों का निर्माण भी करती है।

"रोज़गार और निर्माण" मध्यप्रदेश माध्यम से प्रकाशित होने वाला नियमित साप्ताहिक समाचार-पत्र है। इसकी लगभग 55,000 हजार प्रतियाँ प्रति सप्ताह प्रकाशित होती थी किन्तु कोविड महामारी से लंबे लाकडाउन के फलस्वरूप इसकी लगभग 35 हजार प्रतियाँ प्रति सप्ताह प्रकाशित हो रही है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक यह समाचार-पत्र पहुँचता है। इस समाचार-पत्र के प्रकाशन की नियमितता और गुणवत्ता के कारण इसकी एक विशिष्ट पहचान बनी है।

संचार के इस समय में ग्रामीण संचार की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मासिक पत्रिका **"मध्यप्रदेश पंचायिका"** का प्रकाशन भी पिछले दो दशक से मध्यप्रदेश माध्यम कर रहा है।

वर्ष 2021 के शासकीय कैलेंडर, डायरी का विशेष स्वरूप में आकल्पन किया गया। संस्था द्वारा विशेष मीडिया कैम्पेन्स, इवेंट मैनेजमेंट के लिए आकल्पन, प्रिंट मीडिया, जनसंपर्क विभाग के लिए **उम्मीद** पुस्तक, **विकास के प्रतिबद्ध प्रयास** पुस्तक, **आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश** (हिन्दी/अंग्रेजी) पुस्तक, **मध्यप्रदेश का न्यासिक इतिहास और न्यायालय** (कॉफी टेबल पुस्तक हिन्दी) का आकल्पन तथा **किल कोरोना अभियान**, कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम, गरीब कल्याण सप्ताह, जनजाति गौरव दिवस, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना, उन्नत सिंचाई-समृद्ध किसान, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), पंजीयन विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के लिये विज्ञापनों के आकल्पन का कार्य किया गया।

मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा नमस्ते ओरछा समारोह, विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के उपचार एवं बचाव तथा किसान-कल्याण पर आधारित वृत्तचित्र, टी.वी. स्पोर्ट्स तथा गीत आदि का निर्माण तथा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्रीजी के **आत्म-निर्भर भारत** के संकल्प को लेकर निर्मित काव्य म्यूजिकल वीडियो **हम कर सकते हैं**, को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उल्लेखनीय पुरस्कार तथा नेक्स्ट जनरेशन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बेस्ट शार्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

संस्था के वर्ष 2019-20 तक के अंतिम लेखे तैयार कर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स द्वारा अंकेक्षण किया जा चुका है।

....

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 29 वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विश्वविद्यालय से निकले हजारों विद्यार्थी मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ अपना व्यवसायिक योगदान दे रहे हैं। विगत शैक्षणिक सत्र में कोविड 19 के कारण लगे लॉकडाउन जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी ऑनलाईन अकादमिक कार्य-कलापों के साथ अनेक आयोजनों के माध्यम से विश्वविद्यालय ने अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिये चलने वाली कार्य यात्रा को जारी रखा है।

29 वर्षों की यात्रा में हिन्दी पत्रकारिता पर विशेष फोकस के साथ विश्वविद्यालय पत्रकारिता, जनसंचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षण-प्रशिक्षण, शोध और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में स्थापित हो चुका है। तेजी से विस्तृत हो रहे मीडिया के समग्र क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित पत्रकार और मीडिया व्यवसायी उपलब्ध कराना, हिन्दी और अन्य भाषायी पत्रकारिता के बीच अंतर-संवाद, मीडिया के सामाजिक सरोकारों पर विमर्श एवं मीडिया और संचार के विविध आयामों पर उत्कृष्ट शोध गतिविधियों का संचालन विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य है।

मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रतिष्ठित केंद्र

मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के तीन अन्य परिसर क्रमशः नोएडा, खण्डवा, रीवा, में संचालित हैं। विश्वविद्यालय में मीडिया शिक्षा, मीडिया प्रबंधन, जनसंपर्क, नवीन मीडिया, प्रिंटिंग पैकेजिंग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबद्ध विभिन्न विषयों/संकायों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., पीएच.डी. जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। पुस्तकालय प्रबंधन के क्षेत्र में दक्षता एवं कौशल से पूर्ण मानव संसाधन विकसित करने हेतु इस वर्ष से विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ लायब्रेरी साइंस (B.Lib.Sc) पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग एवं तीन अध्ययन परिसरों में शैक्षणिक सत्र (जुलाई 2020) में कुल 945 विद्यार्थी पंजीकृत हुए।

देशभर में विश्वविद्यालय की 38 मीडिया व 1592 कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों की सहयोगी संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र (जुलाई 2020 से जून 2021) में कुल 60,651 विद्यार्थी पंजीकृत हुए।

इस वर्ष 2019-2020 में संस्थाओं की अकादमिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संकाय विकास कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। अब तक कलाउड कम्प्यूटिंग, एंड्रॉयड, लाईनेक्स आदि पर दो महत्वपूर्ण कार्यशालाएँ संपन्न हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश भर की अध्ययन संस्थाओं में अध्यापनरत शिक्षक लाभांविता हुए हैं।

समस्त आवेदनों के लिए ऑनलाईन सिस्टम की उपलब्धता

इस सिस्टम से विश्वविद्यालय में प्रदेश भर में कार्यरत संबद्ध अध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के साथ ही प्रोविजनल प्रमाण-पत्र, माईग्रेशन, उपाधि आदि के आवेदन करने में सहूलियत हुई है।

पीएच.डी. उपाधियाँ

विश्वविद्यालय के मीडिया एवं कम्प्यूटर संकाय में वर्ष 2020 में 04 पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई है। दिसम्बर 2020 तक कुल 58 पीएच.डी. उपाधियाँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई हैं।

उपाधि शाखा

उपाधि शाखा द्वारा मीडिया एवं कम्प्यूटर पाठ्यक्रम की उपाधि प्रिंटिंग एवं प्रेषण संबंधित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा उपाधि प्राप्त किए जाने हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन किये जाते हैं। जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक 71,300 उपाधियों का प्रेषण/वितरण किया गया है।

डिजिटल इंडिया

विश्वविद्यालय में संपूर्ण प्रवेश, नामांकन, परीक्षा फार्म प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाइन के सहयोग से पूरी तरह ऑनलाइन की जा चुकी है।

प्लेसमेंट

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सामाजिक सरोकारों से प्रतिबद्धता के साथ जन-संचार एवं मीडिया के क्षेत्र में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे रहे हैं। प्लेसमेंट प्रकोष्ठ का कार्य मीडिया संस्थानों और विश्वविद्यालय के बीच संवाद बनाना तथा मीडिया के क्षेत्र में उपलब्ध बेहतर अवसरों के साथ उत्कृष्ट भविष्य के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना है। विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी देश-विदेश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों, सामाजिक प्रतिष्ठानों, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण संगठनों तथा अन्य शासकीय संगठनों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, जो अपने आप में विश्वविद्यालय की साख और गुणवत्ता का परिचायक हैं। विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ने अपनी साख ऐसी बनायी है कि विद्यार्थी अध्ययन के दौरान ही रोजगार पा जाते हैं।

कैम्पस प्लेसमेंट के अन्तर्गत Zee News, Etv Bharat Network 18, सहारा इण्डिया, Jaro Education, वेब दुनिया, सार्थक टी.वी., Aglasem Edutech Gurgaon, Crazy Media Labs, लोकनीति चैनल, Tv 9, Onliy Profit India, Amco N Sons, Duta, Hospibuz तथा दैनिक भास्कर भोपाल, द्वारा आयोजित कैम्पस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कई विजिट आयोजन करवाये गये। साथ ही विभिन्न मीडिया एवं कम्प्यूटर संस्थानों कार्य प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों को भेजा गया, जिससे विद्यार्थियों को रोजगार हेतु चयनित किया गया। इस वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का चयन उपरोक्त कंपनियों के अतिरिक्त कई अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ।

इंटरशिप हेतु विद्यार्थियों को विभिन्न मीडिया संस्थानों, कम्प्यूटर क्षेत्र व अन्य प्रबंधन संस्थानों में भेजा गया।

विश्वविद्यालय के प्रकाशन

अ- प्रकाशित पुस्तकें

- 1- कुलपति संवाद
- 2- हिंदी पत्रकारिता विमर्श

लेखक/संपादक

- डॉ. पवन सिंह मलिक
- लोकेन्द्र सिंह

ब- प्रकाशनाधीन पुस्तकें

- 1- समाज विज्ञान, संचार एवं प्रबंधन में अनुसंधान
कौशल का विकास
- 2- जनसंपर्क एवं निगमित संचार
- 3- स्त्री शक्ति संवाद
- 4- महाभारत में संचार सूत्र
- 5- स्व. मदन मोहन जोशी की पत्रकारिता एवं सिद्धांत

लेखक/संपादक

- डॉ. बीएस नागी
- डॉ. नीमोधर
- डॉ. पी. शशिकला
- प्रो. श्रीकांत सिंह
- पंकज पाठक

विश्वविद्यालय का नवीन परिसर निर्माण

विश्वविद्यालय का अपना नवीन परिसर भोपाल के पास बिसनखेड़ी ग्राम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवंटित 50 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन है। नवीन परिसर परियोजना की कुल लागत रुपए 148.86 करोड़ है। परियोजना के प्रथम चरण में भवन निर्माण की लागत रुपए 116.70 करोड़ है, जिसमें कुल 57,458 वर्ग मीटर फ्लोर एरिया का निर्माण प्रस्तावित है।

कोविड की परिस्थिति के चलते आये अवरोधों को पार कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परियोजना निर्माण कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है।

विश्वविद्यालय में एन.सी.सी.

विश्वविद्यालय में 4MP Batalion NCC, Bhopal, M.P. के पत्र क्रमांक 09/A-I/NCC/Raising/ दिनांक 13 October 2015 पत्र क्रमांक MP&CG Dte./60001/P&C/Re-Org/Bhopal दिनांक 21 October 2015 के अनुसार एन.सी.सी. टूप (यूनिट) खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें विश्वविद्यालय को एक प्लाटून (संख्या 54 (SD/SW), 3 वर्षीय) शासन की ओर से स्वीकृत की गई है।

एन.सी.सी. टूप (यूनिट) में कुल एक प्लाटून (संख्या 54 (SD/SW), 3 वर्षीय) में प्रथम वर्ष में 29, द्वितीय वर्ष में 13 एवं तृतीय वर्ष में 05 कैडेट पंजीकृत हैं। कुल 47 कैडेट नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय के एन.सी.सी. यूनिट के 2 कैडेट, थल सैनिक कैम्प, आई.जी.सी. हेतु, चयनित हुए हैं।

विश्वविद्यालय के एन.सी.सी. यूनिट के 5 कैडेट (स्वतंत्रता दिवस) एवं 2 कैडेट (गणतंत्र दिवस) का चयन, राज्य स्तरीय परेड, लाल परेड हेतु हुआ। एक कैडेट का चयन राष्ट्रीय स्तर के जे. एंड के. कैम्प हेतु, एक कैडेट का चयन राष्ट्रीय स्तर के आल इंडिया ट्रेकिंग कैम्प हेतु, एक कैडेट का चयन राष्ट्रीय स्तर के ई.वी.एस.बी. कैम्प हेतु और एक कैडेट का चयन सेना में जनरल ड्यूटी हेतु हुआ है।

रीवा परिसर

रीवा परिसर में सत्र 2019-20 से नवीन पाठ्यक्रम एम.ए.(पत्रकारिता) आरंभ किया गया। रीवा परिसर हेतु 5 एकड़ भूमि पर नवीन परिसर का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। अगले 4-5 माह में रीवा परिसर एक अत्याधुनिक भवन में प्रारंभ हो जायेगा।

....

भाग-2

बजट (एक दृष्टि में)

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

मांग संख्या - 32 शीर्ष (2220) सूचना तथा प्रचार (आयोजनेतर)

(31.01.2020 की स्थिति में)

(राशि लाख रुपये में)

क्रं.	शीर्ष	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	(2304) निर्देशन और प्रशासन	17063.73	15816.22	9615.63	6950.60
2	(7248) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार	5406.30	5396.93	5400.00	4168.54
3	(5489) पत्रकारिता पुरस्कार प्रशिक्षण	68.20	9.19	68.20	0.98
4	(8688) म.प्र.सूचना केंद्र, नई दिल्ली	151.23	115.58	157.74	81.22
5	(2822) चलचित्र इकाई की स्थापना	672.85	571.40	161.27	148.41
6	(0994) क्षेत्र प्रचार	1818.62	1467.52	1200.00	664.47
7	(4065) विशेष अवसरों पर प्रचार	7112.22	6260.83	6499.40	3867.04
8	(0223) प्रकाशन	498.18	469.99	148.10	94.42
9	(1294) वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को सम्मान निधि	169.00	142.24	249.00	199.10
10	(7437) पत्रकारों को लेपटाप प्रदाय	3.20	2.40	10.00	-
11	(0684) कार्यालय भवन निर्माण	250.00	17.65	500.00	23.24
12	(5620) समन्वित प्रचार-प्रसार	436.47	347.28	300.47	178.58
13	(8808) सूचना प्राद्यौगिकी संबंधी कार्य	32.00	29.26	32.00	17.81
14	(0102) अनुसूचित जनजाति उपयोजना (5621) जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	181.87	-	134.54	69.64
15	(0103) अनुसूचित जाति उपयोजना (5621) जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	201.85	-	149.26	50.30
16.	(9660) प्रिन्ट मीडिया	-	-	7609.62	5126.06
17.	(9852) मीडिया रिसर्च एवं फीड बैक	-	-	0.02	-
	महायोग (मांग संख्या-32)	34065.72	30646.49	32235.25	21640.41

भाग-3

सामान्य प्रशासनिक विषय

सहायक संचालक के 11 सीधी भर्ती के रिक्त पदों का प्रस्ताव प्रतिवेदित अवधि में लोक सेवा आयोग, इंदौर को भेजा गया है। विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के 197 रिक्त पद की पूर्ति का प्रस्ताव पी.ई.बी. को भेजा गया।

विभाग के 03 दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई। प्रतिवेदित अवधि में 08 राजपत्रित अधिकारियों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 63 कर्मचारियों को पात्रतानुसार प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ भी दिया गया।

राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों की पदक्रम सूची 01 अप्रैल 2020 की स्थिति में प्रकाशित की जा चुकी है।

विधानसभा उप चुनाव 2020 के दौरान पेड- न्यूज संबंधी मामले, राष्ट्रीय एवं राज्य- स्तरीय सभी समाचार-पत्र, पत्रिकाओं का परिनिरीक्षण और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों की मानीटरिंग के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के कार्यालय में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को 24 घण्टे सतत् रूप से तैनात किया गया।

कर्मचारी-कल्याण

कर्मचारियों को समय पर समयमान-वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सभी पात्र कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया गया।

विभागीय कर्मचारी संघ की समस्याओं/ कठिनाइयों, मांगों का यथोचित निराकरण संचालनालय स्तर पर किया जाता है।

विभागीय प्रशिक्षण

विभागीय कार्यों एवं दायित्वों का कुशलता एवं दक्षता से निर्वहन करने के लिये जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों का दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से दिनांक 14 दिसम्बर से 17 दिसम्बर, 2020 को आयोजित किया गया।

महिलाकर्मियों की समस्याओं का निराकरण

महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के संबंध में मुख्यालय पर राजपत्रित महिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग में महिलाओं की सर्वाधिक पद-स्थापना मुख्यालय में है। महिलाओं के लिए अलग से प्रसाधन की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अधीनस्थ कार्यालयों में भी महिला कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं। राज्य महिला आयोग के प्रचार-प्रसार कार्यों को संपादित करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी नामांकित है।

....

भाग-4

विभागीय प्रकाशन

जनसंपर्क विभाग द्वारा मासिक "मध्यप्रदेश संदेश" नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा साप्ताहिक "रोजगार और निर्माण" का नियमित प्रकाशन भी हो रहा है।

....

भाग-5

उपसंहार

जनसंपर्क विभाग का प्रमुख कार्य शासन की जन-कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जनता के हित में सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, आकाशवाणी, समाचार-पत्र/ पत्रिकाओं, प्रकाशनों, क्षेत्र प्रचार के पारम्परिक और आधुनिक माध्यमों के साथ ही सोशल-डिजिटल मीडिया के जरिये जन-सामान्य तक पहुँचाना है। विधानसभा उप चुनाव-2020 एवं शासन की गतिविधियों का संचालनालय सहित प्रदेश के सभी जिला जनसंपर्क कार्यालयों द्वारा सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

सूचनाओं के विस्तार के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिला स्तर के समाचारों की उपलब्धता की दृष्टि से विभागीय वेबसाइट www.mpinfo.org, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं की क्लीपिंग के लिये www.mpnewsarch.org, जिलों की खबरों के लिये डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल www.dprmpinfo.org सतत् कार्यशील है। इन साइटों को मौजूदा परिवेश में नवीनतम स्वरूप देकर मोबाईल उपयोगी के साथ यूजर्स फ्रेंडली भी बनाया गया।

....



जनसंपर्क अधिकारियों के दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में 14-15 एवं 16-17 दिसम्बर, 2020 को हुआ।

आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े एवं संचालक जनसंपर्क श्री आशुतोष प्रताप सिंह ने अधिकारियों को सम्बोधित किया।





आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाड़े एवं संचालक जनसंपर्क श्री आशुतोष प्रताप सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंपर्क अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों पर चर्चा करते हुए।